मध्य प्रदेश में इस्पात क्षेत्र में परियोजनाएं

534. **श्री दिलीप सिंह जुदेव :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात क्षेत्र में कितनी परियोजनाएं लागू की जा रही है;

(ख) इन परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है;

(ग) क्या निर्धारित समय से पीछे चल रही परियोजनओं के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आमंत्रित करने का कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ताकि राज्य में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराये जा सके; और

(च)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 11 ग्रीनफ़ील्ड इस्पात परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं । ब्यौरा विवरण में दिया गया है । (**नीचे देखिये**)

(ग) और (घ) विद्यमान निति के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की इस्पात परियोजनाओं की किसी कानून की आवश्यकताओं के अनुसरण में संवीक्षा नहीं की जाती । तथापि इस्पात मंत्रालय परियोजना कार्यान्वयन की किसी समस्या का समाधान करने के लिए उद्योग के साथ आवश्यक रुप से कार्रवाई करता है ।

(ड़) और (च) जुलाइ, 1991 से प्रचालित नई औद्योगिक नीति के तहत लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्‌यगों की सूची से निकाल दिया गया है । स्थान स्थिति संबंधी कतिपय प्रतिबन्धोम की शर्त पर एसे औधोगिक लाइसेंस से भी छूट दे दी गई है । चूंकि इस्पात उद्योग को बाजार के लिए पुर्णतः खोल दिया गया है । इसलिए इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए निवेश संबंधी निर्णय आदि उद्यामियों के लिए वाणिज्यिक निर्णय का मामला है । इस प्रक्रिया में केन्द्र सरकार सुविधा प्रदायक के रुप में कार्य करती है ।

विवरण

कार्यान्वयनाधीन नई/ग्रीन फ़ील्ड इस्पात परियोजनाओं की सूची

क्र0 सं0	इकाई का नाम एवं स्थान	क्षमता (लाख टन) (विक्रेय इस्पात)	निवेश (करोड़ रु0)	चालू करने की स्थिति/तारीख
1.	राजिन्दर स्टील लि0, (रायपुर, मध्य प्रदेश	3.00	500.00	कार्यान्वयनाधीन जून, 98
2.	मालविका स्टील लि0, (जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश)	8.50	1940.00	कार्यान्वयनाधीन मार्च, 99
		(बी एफ़प्रज्वलित, कच्चे लोहे का उत्पादन कर रही है)		
3.	जिन्दल विजय नगर स्टील लि0, (बेल्कारी, कर्नाटक)	15.70	4133.00	कार्यान्वयनाधीन मिल : चालू अन्य इकाइयां :1998-99
4.	साउदर्न आई एण्ड एस कंपनी लि0, (सेलम, तमिलनाडु)	3.00	700.00	कार्यान्वयनाधीन सितंबर, 98
		(बी एफ़प्रज्वलित, कच्चे लोहे का उत्पादन कर रही है)		
5.	एस जे के स्टील कार्पोरेशन लि0, (अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश)	4.00	636.00	कार्यान्वयनाधीन सितंबर, 98
6.	कुमार मेटलर्जिकल कार्पोरेशन लि0, (नालगोंडा, आन्ध्र प्रदेश)	1.25	146.00	कार्यान्वयनाधीन अनुपलब्ध

क्र0 सं0	इकाई का नाम एवं स्थान	क्षमता (लाख टन) (विक्रेय इस्पात)	निवेश (करोड़ रु0)	चालू करने की स्थिति/तारीख
7.	इस्पात इंडस्ट्रीज लि0, (रायगढ़, महाराष्ट्र)	30.00	4845.00	कार्यान्वयनाधीन जुलाई, 98
8.	बेल्लारी एस एंड ए लि0, (बेल्लारी, कर्नाटक)	4.10	891.00	कार्यान्वयनाधीन अक्टूबर, 98
9.	उषा इस्पात लिमिटेड, (सतारा, महाराष्ट्र)	6.00	1425.00	कार्यान्वयनाधीन मई, 98
10.	नीलांचल इस्पात निगम लि0, (डबरी, उडीसा)	6.20	1510.00	कार्यान्वयनाधीन 2000
11.	नोवा स्टील (आई)लि0, (बिलासपुर, मध्य प्रदेश	7.20	140.00	कार्यान्वयनाधीन अनुपलब्ध

Employment Generation in Urban Areas or Some States

535. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of schemes/projects etc. launched/undertaken/financed by Government for employment generation for the educated, uneducated and illiterate youths in Urban area of Madhya Pradesh, Rajasthan and North-Eastern Region during the preceding five years; and

(b) the achievements in different schems. State-wise?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI) (a) Two Centrally Sponsored Schemes, namely Nehru Rojgar Yojana JRY and Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Programme (PMIUPEP) were being implemented by this Ministry in the country including urban areas of Madhya Pradesh, Rajathan and North-Eastern Regions. These two schemes were replaced by a newly launched Programme "Swarna Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY)" w.e.f. 1-12-97.

NRY was being implemented since October, 1989 in the country with the objective of generating self-employment and wage-employment opportunities to the unemployed and under-employed urban poor. The scheme was applicable to households living below the poverty line in urban areas.

PMIUPEP having a component of self-employment through setting up of micro-enterprises was launched in Novermber, 1995.

The maximum unit cost under this component was Rs. 1 lakh and the maximum allowable subsidy was 15% of the project cost subject to a limit of Rs. 7500. The beneficiary was required to contribute 5% of the project cost as margin money.

SJSRY seeks to provide gainful employment to the urban unemployed or under-employed poor through encouraging the setting up of self-employment ventrues of provision of wage employment by utilising their labour for ocnstruction of socially and economically useful public assets. This programme targets the urban poor living below the poverty line, as defined from time to time.

(b) The details of achievements under NRY for North-Eastern States and Madhya Pradesh and Rajasthan are annexed as Statement-I *(See* below) and Statement II *(See* below)

The dealls of ahievements under PMIUPEP are annexed as Statement III *(See* below).

As the SJSRY has been launched recently. States are still in the primary stages of implementation.